

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 मई 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 570वीं बैठक दिनांक 11/05/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्षय महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No 9004/2022 Gwalior Development Authority, Executive Engineer, Vikash Bhavan, Gwalior, MP Prior Environment Clearance for Township Project "Maharajpura Residential Scheme Phase-4 (Shatabdipuram Phase-4)" in Village - Mau and Vikrampur, Tehsil - Grid, Dist. Gwalior, (MP) Total Project Influenced Area-19,25,380.68 M2 Area for Plotted Development- 6,70,131.40 M2, Total no. of residential Units – 5057, Total Shops – 54. Total Project Influenced Area-19,25,380.68 M2, Area for Plotted Development- 6,70,131.40 M2 , Total no. of residential Units – 5057, Total Shops – 54.**

This is case of Prior Environment Clearance for Township Project "Maharajpura Residential Scheme Phase-4 (Shatabdipuram Phase-4)" in Village - Mau and Vikrampur, Tehsil - Grid, Dist. Gwalior, (MP).

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 555th SEAC dated 24/02/2022 wherein ToR was recommended. PP has submitted the EIA report forwarded through SEIAA on-line and the same was scheduled in the agenda.

The case was scheduled for the presentation today in 570th SEAC meeting dated 11.05.2022 but neither the Project Proponent (PP) nor his representative was present to explain the query which might be raised or to make any commitment desired by the

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 मई 2022

committee during the deliberation. However, EIA consultant vide mail dated 09/05/22 requested to differ the case as they are unable to attend the appraisal meeting. Committee decided to call the PP in subsequent meetings giving last chance and even if the PP remains absent, the case shall be returned to SEIAA assuming that PP is not interested to continue with the project.

2. Case No 8370/2021 M/s. Hardoul Granite, Prop. Smt. Krishna Yadav W/o Shri Ashok Singh Yadav, 108, Bankers Colony, Thatipur, Dist. Gwalior, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.320 ha. (150005 cum per annum) (Khasra No. 13h), Village - Lakhanpura, Tehsil - Dabra, Dist. Gwalior (MP) EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 13h), Village - Lakhanpura, Tehsil - Dabra, Dist. Gwalior (MP) 2.320 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 493वीं दिनांक 23/03/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

आज दिनांक 11/05/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन-लाईन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह प्रकरण क्षमता विस्तार का है जिसमें पूर्व में 80,000 घनमीटर / वर्ष की क्षमता से 1,50,005 घनमीटर/वर्ष की क्षमता की जाना प्रस्तावित है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया उनके द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व की पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है, जो उनके पत्र क्रमांक 082 दिनांक 15/03/2022 द्वारा जारी किया गया है । जारी किए गए पालन प्रतिवेदन में कोई भी नॉन कम्प्लाइंस नहीं पाई गई । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा यह खदान वर्ष 2021 में पूर्व की लीजधारक से अपने नाम स्थानांतरित कराई गई है तथा उनके द्वारा अभी कोई उत्खनन कार्य नहीं किया गया है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह भी बताया कि पूर्व के लीजधारक द्वारा बैरियर जोन में समुचित वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है जबकि डिया से प्राप्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार 45 वृक्ष प्रति हेक्टेयर (कम से कम 100) लगाये जाने थे, अतः उनके द्वारा लगभग 200 पेड़ों का वृक्षारोपण खनन क्षेत्र में किया गया है जिसके फोटोग्राफ्स प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न है । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान के पूर्वी क्षेत्र में

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 मई 2022

एक पिट है जिसमें पानी भरा है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह माइंड आऊट पिट है जिसमें से माइन प्लान के अनुसार लगभग 37,842 घनमीटर पत्थर निकाला जा चुका है तथा पूर्व के खदान मालिक द्वारा वर्ष 2017-18 में उत्खनन कार्य किया गया है एवं तत्पश्चात् खदान में कार्य बंद है। प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि खदान क्षेत्र के दक्षिण भाग से एक कच्ची रोड़ निकल रही है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तुतीकरण में इस कच्ची रोड़ के संरक्षण हेतु 10 मीटर का सेट-बैक (7.5 मीटर का बैरियर जोन छोड़कर) प्रस्तावित किया गया है तथा खनन के इस क्षेत्र में हाई डेनसिटी प्लांटेशन किया जाना प्रस्तावित किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण एवं सामाजिक कल्याण के कार्य (जैसे स्कूल में खेल सामग्री, शौचालय हेतु हेण्डपम्प वाटर टैंक, पेय जल की व्यवस्था) किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । ई.आई.ए. रिपोर्ट में उत्पादन क्षमता टन / वर्ष उल्लेखित है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह टंकण त्रुटि है, हम ई.आई.ए. रिपोर्ट सुधार कर आज प्रस्तुत कर रहे हैं । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-10(i) में परियोजना की लागत रु. 30 करोड़ दिखाई गई है, कृपया स्पष्ट करें ।
- ✓ फार्म-2 अनुसार पी.एम.-10 की वैल्यू 96 है, कृपया इसको कम करने के सुझाव प्रस्तावित करें ।
- ✓ फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-32(3) के अनुसार खनन क्षेत्र में 1200 पौधे लगे हैं, कृपया स्थिति स्पष्ट करें ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 11/05/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन -1,50,005 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु.13.19 लाख एवं रिकरिंग 08.63 लाख प्रति वर्ष ।

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 मई 2022

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 02.00 लाख :-

क्रं.	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
1.	ग्राम लखनपुरा के प्रथमिक विद्यालय में 01 हैण्ड पंप व 2000 लीटर ओवरहेड टैंक बनाकर शौचालय में पानी की व्यवस्था किया जायेगा तथा उचित जल चैनलाइजेशन सिस्टम के साथ।	70,000
2.	ग्राम लखनपुरा के प्रथमिक विद्यालय में खेदकूद सामग्री का वितरण।	20,000
3.	ग्राम लखनपुरा में मास्क एवं हैंड सेनेटाइजर का वितरण।	10,000
4.	पोर्टेबल ई.सी.जी. मशीन, व्हील चेर, तथा स्ट्रेचर का वितरण पी.एच. सी. लखनपुरा में किया जायेगा।	1,00,000
योग		2,00,000
संबंधित पी.एच.सी. में पदस्थ चिकित्सक के सुझाव अनुसार उपरोक्त इवेंट्री में परिवर्तन किया जा सकेगा।		

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4000 वृक्षों का वृक्षारोपण :

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	शीशम, नीम, चिरौल, पीपल, बरगद, खमैर, सीताफल, करंज, अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	2000
2.	लखनपुरा के शासकीय विद्यालय में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, गुलमोहर।	10
3	ग्रामपंचायत लखनपुरा के ग्रामवासियों को वितरण हेतु	आवंला, आम, अमरुद, जामुन, सीताफल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ।	490
4.	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1500
कुल			4000

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 मई 2022

3. Case No 9142/2022 M/s Kisan Exports, Khedia Bhawan, P.O. Bijuri, Tehsil - Kotma, Dist. Anuppur, MP - 484440 Prior Environment Clearance for Granite Quarry in an area of 3.0 ha. (Granite Block - 1591 cum per annum, Saleable Stone Waste - 9017 cum per annum) (Khasra No. 1664), Village - Cholna, Tehsil - Jaithari, Dist. Anuppur (MP) EIA Consultant: Green Circle Vadodara (Guj.)

This is case of Granite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 1664), Village - Cholna, Tehsil - Jaithari, Dist. Anuppur (MP) 3.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 11/05/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 673 दिनांक 18/04/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 9.0 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण पश्चिम दिशा में 40 मीटर पर तथा पूर्व दिशा में 275 मीटर पर रिहायशी मकान/आबादी दिख रही है तथा पश्चिम दिशा में 65 मीटर पर तालाब, पूर्व दिशा में 310 मीटर पर पक्का रोड़ तथा पश्चिम दिशा में 18 मीटर पर कच्चा रोड़ है। अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में इनकी संरक्षण योजना प्रस्तुत की जानी होगी। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि लीज क्षेत्र में कई पेड़ (40-50) हैं अतः इनकी ट्री इन्वेट्री मय प्रजाति का नाम, ऊंचाई एवं गirth सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण में ग्रेनाइट उत्खनन होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. दक्षिण पश्चिम दिशा में 40 मीटर पर तथा पूर्व दिशा में 275 मीटर पर रिहायशी मकान/आबादी दिख रहा है तथा पश्चिम दिशा में 65 मीटर पर तालाब, पूर्व दिशा में 310 मीटर पर पक्का रोड़ तथा पश्चिम दिशा में 18 मीटर पर कच्चा रोड़ है। अतः ई.आई.एम रिपोर्ट में इनकी संरक्षण योजना प्रस्तुत की जानी होगी।

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 मई 2022

2. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन केंशरो का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
3. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
4. लीज क्षेत्र में कई पेड (40-50) हैं अतः फोटो सहित उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गर्थ सहित विवरण मय संरक्षण योजना के ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
5. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
6. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. Study of Eco System Services with special reference to water recharging, wild life value, fauna value and MFP values shall be carried out from a reputed expert agency and same shall be submitted with EIA report.

4. Case No 9144/2022 M/s Kisan Exports, Khedia Bhawan, P.O. Bijuri, Tehsil - Kotma, Dist. Anuppur, MP - 484440 Prior Environment Clearance for Granite Quarry in an area of 10.926 ha. (Granite Block - 10011 cum per annum, Saleable Stone Waste - 56727 cum per annum) (Khasra No. 1578, 1579, 1583/1/2, 2074), Village - Cholna, Tehsil - Jaithari, Dist. Anuppur (MP) EIA Consultant: Green Circle Vadodara (Guj.)

This is case of Granite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 1578, 1579, 1583/1/2, 2074), Village - Cholna, Tehsil - Jaithari, Dist. Anuppur (MP) 10.926 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 11/05/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 671 दिनांक 16/04/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 24.77 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 मई 2022

प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण-पूर्वी दिशा में 100 मीटर पर रिहायशी मकान/आबादी दिख रही है तथा लीज क्षेत्र के बीचोबीच से एक कच्चा रास्ता निकल रहा है । अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में इनकी संरक्षण योजना प्रस्तुत की जानी होगी । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि लीज क्षेत्र में कई पेड़ (80-100) हैं अतः इनकी ट्री इन्वेट्री मय प्रजाति का नाम, ऊँचाई एवं गirth सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण में ग्रेनाइट उत्खनन होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण-पूर्वी दिशा में 100 मीटर पर रिहायशी मकान/आबादी दिख रही है तथा लीज क्षेत्र के बीचोबीच से एक कच्चा रास्ता निकल रहा है । अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में इनकी संरक्षण योजना प्रस्तुत की जानी होगी ।
2. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्वेंशरो का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
3. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
4. लीज क्षेत्र में कई पेड़ (40-50) हैं अतः फोटो सहित उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गirth सहित विवरण मय संरक्षण योजना के ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
5. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
6. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. Study of Eco System Services with special reference to water recharging, wild life value, fauna value and MFP values shall be carried out from a reputed expert agency and same shall be submitted with EIA report.

5. Case No 9150/2022 Smt. Sumitra Grover Owner, Village - Badagaon, Tehsil - Barhi, Dist. Katni (MP) 483501 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.61 ha. (54405 cum per annum) (Khasra No. 135/1, 135/2, 135/3, 136), Village - Badagaon, Tehsil - Barhi, Dist. Katni (MP) Env. Consultant M/s. Amaltas Enviro Industrial Consultants LLP,

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 135/1, 135/2, 135/3, 136), Village -

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 मई 2022

Badagaon, Tehsil - Barhi, Dist. Katni (MP) 1.61 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 11/05/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 290 दिनांक 27/01/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 7.48 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर-पूर्वी दिशा में 140 मीटर पर पक्का रोड़, दक्षिण-पूर्वी दिशा में 580 मीटर पर आबादी एवं दक्षिण-पश्चिम दिशा में 480 मीटर पर प्राकृतिक नाला है। अतः उसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत की जानी होगी। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि लीज क्षेत्र में 02 पेड़ हैं अतः ट्री इन्वेन्ट्री मय प्रजाति का नाम, ऊंचाई एवं गirth सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. खदान के उत्तर-पूर्वी दिशा में 140 मीटर पर पक्का रोड़, दक्षिण-पूर्वी दिशा में 580 मीटर पर आबादी एवं दक्षिण-पश्चिम दिशा में 480 मीटर पर प्राकृतिक नाला है। अतः उसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत की जानी होगी।
2. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन केंशरो का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
3. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
4. खनन क्षेत्र में 02 पेड़ हैं अतः फोटो सहित उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गirth सहित विवरण मय संरक्षण योजना के ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
5. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 मई 2022

6. Case No 9151/2022 Smt. Kalibai Wasunia, Owner C.L. Sarnani, Bijalpur, Dist. Ujjain, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 7.0 ha. (200000 cum per annum) (Khasra No. 311), Village - Guani Khalsa, Tehsil - Ujjain, Dist. Ujjain (MP) Consultant Shri Amit Saxena Apex Mintech Udaypur (Rj.)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 311), Village - Guani Khalsa, Tehsil - Ujjain, Dist. Ujjain (MP) 7.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 11/05/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 568 दिनांक 18/04/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 14 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 45.900 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण दिशा में 230 मीटर पर कच्चा रोड़ है। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि लीज क्षेत्र बीच से खुदा हुआ है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया उनको खदान नवम्बर, 21 में आवंटित हुई है तथा आवंटन के पूर्व से ही यह क्षेत्र खुदा हुआ है जिसमें पहले अस्थाई अनुज्ञा पर कार्य हुआ है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया इसका विवरण अनुमोदित माइन प्लॉन में दिया गया है जिसमें 4,02,528 घनमीटर पत्थर का उत्खनन हो चुका है तथा उसे सरफेस मैप पर भी दिखाया गया है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. लीज क्षेत्र बीच से खुदा हुआ है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया उनको खदान नवम्बर, 21 में आवंटित हुई है तथा आवंटन के पूर्व से ही यह क्षेत्र खुदा हुआ है जिसमें पहले अस्थाई अनुज्ञा पर कार्य हुआ है, अतः सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अस्थाई अनुज्ञा से संबंधित दस्तावेज ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें।
2. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन केंशरो का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 मई 2022

3. यदि भू-जल का प्रतिष्ठेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
 4. खनन क्षेत्र में पानी भरा हुआ है, अतः डी-वाटरिंग प्लान ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
 5. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. **प्रकरण क्रमांक 8963/2022 – मेसर्स न्यू जय दाऊबाबा स्टोन क्रेशर, श्री सरदार सिंह गुर्जर, पारस विहार कालोनी, झौंसी रोड़ थाना के सामने, लश्कर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 2724/ min-2, 2725, 2729, 2730, 2728/ min-2, रकबा 2.603 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 60,00 मी.³, ग्राम बिलौआ तहसील डबरा जिला ग्वालियर के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्। Env. Consultant - Shri Amit Saxena Apex Mintech Udaypur (Rj.)**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 2724/ min-2, 2725, 2729, 2730, 2728/ min-2, रकबा 2.603 हेक्टेयर, ग्राम बिलौआ तहसील डबरा जिला ग्वालियर .प्र. पर स्थित है ।

आज दिनांक 15/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर एकल प्रमाण-पत्र (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 9888 दिनांक 03/01/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 07. अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 13.907 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक कि सेक की 549वीं बैठक दिनांक 15/02/22 में इसका प्रस्तुतीकरण हुआ 60,000 घनमीटर/वर्ष की उत्पादन क्षमता के लिए हुआ था किंतु लिपिकीय त्रुटिवश अनुशंसा 6,000 घनमीटर/वर्ष हो गई तथा इसी आधार पर सिया द्वारा भी टॉर 6,000 घनमीटर/वर्ष हेतु जारी कर दिया गया है । मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों में उत्पादन क्षमता 60,000 घनमीटर/वर्ष दर्शाई गई है । अतः उनके द्वारा टॉर संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है । समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा यह पाया कि लिपिकीय त्रुटिवश गलत मात्रा टंकित हो गई थी । अतः समिति अपनी 549वीं बैठक दिनांक 15/02/2022 में टॉर हेतु अनुशंसित स्टोन-6,000 घनमीटर/वर्ष के स्थान पर स्टोन-60,000 घनमीटर/वर्ष किये जाने हेतु संशोधित टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है, शेष शर्तें यथावत रहेंगी ।

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 मई 2022

8. Case No 9137/2022 Shri Shiv Narayan Malviya, Owner, Village - Lagsari, Tehsil - Kukshi, Dist. Dhar, MP - 454001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (10000 cum per annum) (Khasra No. 196/1, 198, 197), Village - Undali, Tehsil - Kukshi, Dist. Dhar (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 196/1, 198, 197), Village - Undali, Tehsil - Kukshi, Dist. Dhar (MP) 1.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 11/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 471 दिनांक 29/03/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य 02 खदान स्वीकृत/संचालित है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 4.50 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल पूर्व से खुदा हुआ है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया उनको खदान 03 फरवरी, 22 को आवंटित हुई है तथा आवंटन के पूर्व से ही यह क्षेत्र खुदा हुआ है, जिसका विवरण अनुमोदित माइन प्लॉन में दिया गया है जिसमें 21,264 घनमीटर पत्थर का उत्खनन हो चुका है तथा उसे सरफेस मैप पर भी दिखाया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उत्खनन हेतु लीज विद्यमान 02 पेड़ काटे जायेंगे तथा उनके एवज में 20 अतिरिक्त पेड़ उसी प्रजाति के लगाये जायेंगे । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान के उत्तरी भाग से 10 मीटर की दूरी पर नाला निकल रहा है, अतः 40 मीटर का सेट-बैक छोड़ा जाये । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-17 में प्लाई एश दिखाई गई है, इसके संबंध में स्थिति स्पष्ट करें।
- ✓ खदान के उत्तरी भाग से 10 मीटर की दूरी पर नाला निकल रहा है, अतः 40 मीटर का सेट-बैक नॉन माइनिंग छोड़ा जाये ।
- ✓ लीज क्षेत्र में 02 पेड़ लगे हैं, जिन्हें काटा जाना प्रस्तावित किया गया है, अतः उसके एवज में उसी प्रजाति के 20 अतिरिक्त पेड़ों के साथ पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.एस.आर. योजना ।

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 मई 2022

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 11/05/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन-10,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.46 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.73 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.85 लाख :-

क्र.	प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु.)
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टाण्डा में मेडोनिक्स का इसीजी मशीन के साथ रिपोर्ट	50,000/-
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टाण्डा में गोदरेज का ए सी 1. 5 टन	35000/-
	कुल	85,000
संबंधित पी.एच.सी. में पदस्थ चिकित्सक के सुझाव अनुसार उपरोक्त इवेंट्री में परिवर्तन किया जा सकेगा।		

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :

क्रमांक	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बेरियर ज़ोन	नीम, सीताफल, पीपल, कचनार, करझ, चिरोल, जलाल जलेबी, सिस्सू आदि।	250
2	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करझ, कदम, चिरोल आदि ट्री गार्ड सहित।	550
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरुद, आबुला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	400
Total			1200

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 मई 2022

9. Case No 9138/2022 Shri Kamran Khan, Owner, 105, Badribagh Colony, Manik Bagh Road, Dist. Indore, MP - 454001, Prior Environment Clearance for Stone & M-sand Quarry in an area of 4.0 ha. (Stone - 25000 cum per annum, M-sand - 75000 cum per annum) (Khasra No. 181/2), Village - Nimola, Tehsil - Dharampuri, Dist. Dhar (MP)

This is case of Stone & M-sand Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 181/2), Village - Nimola, Tehsil - Dharampuri, Dist. Dhar (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 11/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल-पत्र क्रमांक 466 दिनांक 29/03/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान सील के दक्षिण दिशा में 165 मीटर पर नर्मदा नदी है। लीज क्षेत्र 18 पेड़ है जो काटे जायेंगे एवं उनके एवज में 180 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ फार्म-2 में लैंड फारेस्ट लैंड दिखाई है, इसके संबंध में स्थिति स्पष्ट करें।
- ✓ प्रस्तावित एम-सेंड प्लांट नर्मदा नदी के एच.एफ.एल. से कितना दूर है, की सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रायित जानकारी प्रस्तुत करें।
- ✓ एम-सेंड प्लांट 13 कइस-आउट को सरफेस मैप पर दिखाया जाये।
- ✓ एम-सेंड प्लांट से उत्पन्न होने वाले दूषित जल के गोदण की व्यवस्था तथा उत्पन्न होने वाले सिल्ट के अपवहन का विवरण प्रस्तुत करें।
- ✓ भूमि क्षरण रोकने हेतु लीज क्षेत्र के नीचे (नर्मदा नदी की ओर) खाली पड़ी ग्रासकीय भूमि में बैम्बू के सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
- ✓ चूंकि लीज क्षेत्र नर्मदा नदी के पास (लगभग 165 मीटर दूर) स्थित है, अतः बारिश के पानी के उचित निस्तारण की व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत करें।

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 मई 2022

- ✓ प्रस्तावित किये गये गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के डायमेंशन तथा उसमें स्टोन पिचिंग का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण एवं ई.एम.पी. योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.एस.आर. योजना ।

10. Case No 9139/2022 Shri Yagya Jat, Owner, 107/1, Trimurti Nagar, Dist. Dhar, MP – 454001 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (21000 cum per annum) (Khasra No. 958 Peki), Village – Khareli, Tehsil – Sardarpur, Dist. Dhar (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 958 Peki), Village – Khareli, Tehsil – Sardarpur, Dist. Dhar (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 11/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल-पत्र क्रमांक 470 दिनांक 29/03/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान सील के पूर्व दिशा में 100 मीटर औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहा है तथा पश्चिम क्षेत्र में लीज के कुछ भाग में खुदाई की गई है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया स्थानीय ग्रामीणों वहाँ ऊपर की मिट्टी निकाल ली गई है, जिसके कारण वहाँ पर गढ़वा दिख रहा है तथा औद्योगिक क्षेत्र में सिर्फ अभी अधोसंरचना का विकास हो रहा है जो खदान क्षेत्र से 100 मीटर की दूरी पर है । समिति ने चर्चा उपरांत यह अनुशंसा की कि चूंकि लीज 10 वर्ग हेतु स्वीकृत है एवं इस दौरान औद्योगिक गतिविधियाँ प्रारंभ होने से इंकार नहीं किया जा सकता है, अतः 100 मीटर का सेट-बैक खनन क्षेत्र से छोड़ा जाना होगा । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि पूरे खनन क्षेत्र तथा आसपास के क्षेत्र में कंटूर ट्रेंच खुदे हैं, परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन क्षेत्र आसकीय भूमि में है, जो उनको सरकार द्वारा आवंटित की गई है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया 14 कइस क्षेत्र में माईनिंग करके जो पिट बनेगा उससे ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज होगा एवं उनको आवंटित क्षेत्र में बाकी बचे हुए ट्रेंच में उनके द्वारा वृक्षारोपण किया जावेगा।

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 मई 2022

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ औद्योगिक क्षेत्र के कारण 100 मीटर का सेट-बैक (नॉन माईनिंग जोन) दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मैप ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.एस.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 11/05/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतो ाजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतो ाजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन- 21000 मी³ प्रति व र्ग ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.25 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.92 लाख प्रति व र्ग ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.10 लाख :-

वर्ष	प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू.)
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरदारपुर में गोदरेज का ए सी 1. 5 टन का दिया जायेगा	50,000
2	ऑटो क्लेव वर्टिकल 50 एल टी आर	60,000
Total		1,10,000
संबंधित पी.एच.सी. में पदस्थ चिकित्सक के सुझाव अनुसार उपरोक्त इवेंट्री में परिवर्तन किया जा सकेगा ।		

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 व र्ग तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :

क्रमांक	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत सीन	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बेरियर ज़ोन में	नीम, सीताफल, पीपल, कचनार, चिरोल खमेर, जश्जाल जलेबी, सिस्सू आदि।	570

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 मई 2022

2	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि ट्री गार्ड के साथ में	350
.3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आबुला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	1480
योग			2400

11. Case No 9146/2022 Shri Mahi Pal Singh, Owner, Village – Sagraana, Tehsil & Dist. Neemuch, MP – 458441, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.4256 ha. (6000 cum per annum) (Khasra No. 441), Village – Sagraana, Tehsil – Neemuch, Dist. Neemuch (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 441), Village – Sagraana, Tehsil – Neemuch, Dist. Neemuch (MP) 1.4256 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

टाज दिनांक 11/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल-पत्र क्रमांक 417 दिनांक 28/03/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान सील के दक्षिण-पश्चिम दिशा में 175 मीटर पर नाला है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि लीज का दक्षिणी भाग खुदा हुआ है, जिसमें फरवरी, 2020 से उत्खनन कार्य होता दिख रहा है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनको यह लीज फरवरी, 2022 में आवंटित हुई है तब भी यह क्षेत्र खुदा हुआ था जिसका उल्लेख अनुमोदित खनन योजना में किया गया जिसके अनुसार 4,628 घनमीटर पत्थर का उत्खनन किया गया है तथा सरफेस मेप पर दिखाया गया है। इसी प्रकार आवंटित क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र एवं दक्षिण क्षेत्र में एक-एक खदान स्थित है जिसका उल्लेख खनिज अधिकारी ने अपने प्रमाण-पत्र में नहीं किया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पुरानी खदान है जो क्रमशः 2012-13 एवं 2006-07 से कार्यरत थी जिसकी अवधि समाप्त हो गई है, इस कारण खनिज अधिकारी ने अपने प्रमाण-पत्र में इसका उल्लेख नहीं किया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि लीज क्षेत्र के पूर्वी भाग से 20 मीटर की दूरी पर एक

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 मई 2022

एच.टी. लाईन निकल रही है जिस हेतु 30 मीटर का सेट-बैक छोड़ा जाना चाहिए तथा छोड़े गये नॉन माईनिंग क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ लीज क्षेत्र के पूर्वी भाग से 20 मीटर की दूरी पर एक एच.टी. लाईन निकल रही है जिस हेतु 30 मीटर का सेट-बैक (नॉन माईनिंग जोन) दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मैप ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.एस.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 11/05/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतो ज्ञनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतो ज्ञनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट तर्कों एवं स्टैण्डर्ड तर्कों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन- 6000 मी³ प्रति वर्ग फीट ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 10.00 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.77 लाख प्रति वर्ग फीट ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.90 लाख :-

प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु.)
ग्राम सागरना के सरकारी माध्यमिक विद्यालय के परिसर में पत्थर हटाकर भराव करवाया जायेगा और उसे समतल बनाया जायेगा।	90,000/-
कुल	90,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ग फीट तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1700 वृक्षों का वृक्षारोपण :

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत सीमा	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बेरियर जोन में	नीम, सीताफल, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, जलजलेबी, सिस्सू आदि।	550
2	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि ट्री गाईड सहित ।	320

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 मई 2022

3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आबला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	830
Total			1700

12. Case No 9147/2022 Shri Parth Patidar, Owner| Ward No. 12, Bawadi Mohalla, Dhamnod, Tehsil – Dharmपुरी, Dist. Dhar, MP – 454001, Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 1.518 ha. (25000 cum per annum) (Khasra No. 2 Peki), Village – Kunda, Tehsil – Dharmपुरी, Dist. Dhar (MP)

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 2 Peki), Village – Kunda, Tehsil – Dharmपुरी, Dist. Dhar (MP) 1.518 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

टाज दिनांक 11/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन गाँवा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 467 दिनांक 29/03/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान सील के उत्तर-पूर्वी दिशा में 10 मीटर पर रोड़ है, अतः 90 मीटर का सेट-बैक छोड़ा जाना होगा। इसी प्रकार उत्तर दिशा में 20 मीटर पर आवासीय क्षेत्र है, अतः 80 मीटर का सेट-बैक छोड़ा जाना होगा। लीज क्षेत्र 10-12 पेड़ लगे हैं, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि चूँकि प्रकरण मुरुम उत्खनन का है, अतः अधिक से अधिक पेड़ों को बचाया जायेगा तथा उनके चारों ओर एक मीटर का गोलाकार क्षेत्र नॉन माईनिंग जोन छोड़ा जायेगा ताकि खनन के प्रभाव से पेड़ न टूट न हों। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि चूँकि मुरुम खनन का है अतः ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ प्रश्नाधीन खदान सील के उत्तर-पूर्वी दिशा में 10 मीटर पर रोड़ है, अतः 90 मीटर का सेट-बैक (नॉन माईनिंग जोन) दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप।
- ✓ उत्तर दिशा में 20 मीटर पर आवासीय क्षेत्र है, अतः 80 मीटर का सेट-बैक (नॉन माईनिंग जोन) दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप।

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 मई 2022

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.एस.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 11/05/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतो अजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतो अजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट तर्कों एवं स्टैण्डर्ड तर्कों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मरुम- 25,000 मी³ प्रति वर्ग ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 10.43 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.63 लाख प्रति वर्ग ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.20 लाख :-

क्रमांक	प्रस्तावित गतिविधि	वार्षिक आवर्ती व्यय रु.
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धरमपुरी में मेडोनिक्स का इ सी जी मशीन के साथ रिपोर्ट	60,000
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धरमपुरी रेडिएट वॉर्मर दिया जायेगा	35,000
3.	ग्राम कुण्डा में चिकित्सा जाँच शिविरों का आयोजन एवं दवाओं का वितरण किया जायगा	25,000
कुल योग		1,20,000
संबंधित पी.एच.सी. में पदस्थ चिकित्सक के सुझाव अनुसार उपरोक्त इवेंट्री में परिवर्तन किया जा सकेगा ।		

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ग तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1830 वृक्षों का वृक्षारोपण :

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत सीन	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बेरियर ज़ोन में	नीम, सीताफल, चिरोल, पीपल, करंज, जखाल जलेबी, सिस्सू आदि।	500

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 मई 2022

2	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, करछ, कदम, चिरोल, आदि ट्री गार्ड के साथ में	350
3-	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरुद, आबला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	980
Total			1830

?

13. Case No 9149/2022 Shri Rahul Choudhary, Owner, Ranipura, Tehsil & Dist. Dhar, MP - 454001 Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 1.0 ha. (15000 cum per annum) (Khasra No. 374 Peki), Village - Sagadi, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar (MP)

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 374 Peki), Village - Sagadi, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar (MP) 1.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 11/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल-पत्र क्रमांक 465 दिनांक 29/03/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के दक्षिण-पूर्वी दिशा में 50 मीटर पर आबादी है, अतः 50 मीटर का सेट-बैक छोड़ा जाना होगा। खदान क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 75 मीटर पर कच्चा रोड़ है तथा पूर्व दिशा में 50 मीटर रोड़ है, अतः 50 मीटर का सेट-बैक छोड़ा जाना होगा। चूंकि प्रकरण मुरुम का है, अतः ब्लस्टिंग प्रस्तावित नहीं है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ दक्षिण-पूर्वी दिशा में 50 मीटर पर आवासीय क्षेत्र है, अतः 50 मीटर का सेट-बैक (नॉन माईनिंग जोन) दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप।

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 मई 2022

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.एस.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 11/05/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मरुम- 15,000 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 05.30 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.63 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.20 लाख :-

प्रस्तावित गतिविधि	वार्षिक आवर्ती व्यय रु.
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीथमपुर में आवश्यकता अनुसार चिकित्सा उपकरण प्रदान किये जाएंगे	53,000
ग्राम सगड़ी के प्राथमिक विद्यालय में स्त्री और पुरुष शौचालय की मरम्मत और रक्षा रोगन का कार्य किया जायेगा	67,000
कुल योग	1,20,000
संबंधित पी.एच.सी. में पदस्थ चिकित्सक के सुझाव अनुसार उपरोक्त इवेंट्री में परिवर्तन किया जा सकेगा ।	

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बेरियर जोन में	नीम, सीताफल, पीपल, करज, चिरोल, जखाल जलेबी, सिस्सू आदि।	400
2	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करज, कदम, चिरोल, आदि ट्री गार्ड के साथ में	50
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरुद, आबुला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	500

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 मई 2022

4.	पट्टा क्षेत्र में जहा पर खनन कार्य नहीं किया (0.2056 है.) जायेगा वहा पर पौधे लगाए जायेंगे	नीम, सीताफल, पीपल, करझ, चिरोल, जङ्गल जलेबी, सिस्सू आदि।	250
Total			1200

14. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला रायसेन (म.प्र.) ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 318 दिनांक 05/05/22 के माध्यम से रायसेन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 04/05/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 570वीं बैठक दिनांक 11/05/22 में प्रस्तावित की गई । कार्यालय (खनिज शाखा) जिला रायसेन म.प्र. ने पत्र क्रमांक-297/खनिज/2022, दिनांक 09/05/22 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में टंकण त्रुटि होने के कारण पृष्ठ क्रमांक-67, 68, 69, 71, 72 एवं 73 में सुधार कर पुनः जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में संलग्न करने हेतु प्रेषित किया है ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 570वीं बैठक दिनांक 11/05/22 में रायसेन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई, चर्चा के दौरान खनिज विभाग, रायसेन की ओर से श्री राजीव निगम, खनिज निरीक्षक उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :-

- ✓ कार्यालय (खनिज शाखा) जिला रायसेन म.प्र. ने पत्र क्रमांक-297/खनिज/2022, दिनांक 09/05/22 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में टंकण त्रुटि होने के कारण सुधार कर पुनः जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में संलग्न करने हेतु प्रेषित किया है तथा अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आमजनों के सुझाव हेतु उसे पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया था जिसमें 03 व्यक्तियों के सुझाव प्राप्त हुए थे जिनका समायोजन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में किया गया है।
- ✓ राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 318 दिनांक 05/05/22 के माध्यम से रायसेन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार अधिकांश जानकारीयों समाहित की गई है बिंदु क्रमांक-26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोड़कर) से संबंधित है, के अवलोकन से ज्ञात होता है कि रायसेन जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों की जानकारी दी गई है तथा पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी की तालिका एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत किये हैं ।

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 मई 2022

परंतु कुछ संचालित खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी दी गई है तथा कुछ में नहीं दी गई है जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए । साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए । अतः समिति का सुझाव है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन किया जाये उसमें बिंदु क्रमांक-30 की जानकारी (एमओईएफ नोटिफिकेशन, 25/07/2018 के अनुसार बिंदु क्रमांक 26) सभी संचालित खदानों बावत् समाहित की जाये ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि रायसेन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आमजन के सुझाव आमंत्रित कर इनका अनुमोदन जिले में गठित समिति (बैठक दिनांक 29/04/22 में) द्वारा किया जा चुका है । अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ रायसेन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है तथा प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 मई 2022

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 मई 2022

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.)
 - c. Production capacity of the project.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 मई 2022

36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

37. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 मई 2022

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{\text{th}}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 मई 2022

- b. Mining Lease area of the project (in ha.)
c. Production capacity of the project.
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
- The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
 - After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
38. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 मई 2022

- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- ‘C’

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 मई 2022

14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.)
 - c. Production capacity of the project.
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 मई 2022

fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Anganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधों के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 मई 2022

2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 मई 2022

27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna".
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The undertaking inter-alia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.

570वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 मई 2022

- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.